>

Title: Alleged irregularities in the implementation of 'Sarva Shiksha Abhiyan' in the country.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। भारत सरकार की अनेक योजनाओं में सर्वशिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष 2001-02 में शुरू की गयी यह योजना, सर्वशिक्षा अभियान देश के कोने-कोने में सभी बच्चों को मौलिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। आज यह कार्यक्रम पूरे देश में फैल चुका है और 11 लाख आवासों में 19.2 करोड़ बच्चों की जरूरतों को सामने लाता है। इस योजना में 8.5 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय आते हैं और योजना के अंतर्गत 33 लाख शिक्षक-शिक्षिका आ रहे हैं। इस सब का उद्देश्य घर-घर शिक्षा की रोशनी पहुंचाना है । इतनी उदात्त ध्येय वाली योजना वास्तव में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पायी है। इसके कारणों का विश्लेषण अत्यन्त जरूरी है - जैसे कि नःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिशिष्ट में शिक्षक छात्र का अनुपात तय किया गया है, किन्तु वास्तविकता हर प्रदेश में भिन्न-भिन्न है। कहीं-कहीं पर शिक्षक बिना स्कूल चल रहे हैं, तो कहीं पर एक छात्रा के लिए तीन शिक्षक हैं। दोपहर के भोजन में खरीदारी, वितरण, रख-रखाव और खाना पकाने में गड़बड़ियां हो रही हैं। किचन शेड के अनुदानों में घोटाले, मुक्त किताबों की खरीद-वितरण और परिवहन ठेका में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूली शिक्षा मुहैय्या कराने के लिए ब्रिटेन ने भारत को करीब 33 अरब 25 करोड़ रूपए की मदद दी, इस रकम में से करीब 480 करोड़ रूपए की भेंट चढ़ गए। ब्रिटेन ने धन के दुरूपयोग पर जांच तक बैठा दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि शिक्षा की विभिन्न योजनाओं की ओर पूरा ध्यान दिया जाए और सर्वशिक्षा अभियान को, सर्वभ्रष्ट अभियान बनने से बचाया जाए तथा भवन, पेयजल, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराये जाएं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं।